DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला नई दिल्ली | शुक्रवार, 3 फरवरी 2023

केजरीवाल-सिसोदिया कर रहे गुमराह: बिधूड़ी

अमर उजाला ब्यूरो

नेता प्रतिपक्ष ने कहा- बजट में दिल्ली को 325 करोड़ नहीं, डेढ़ लाख करोड़ रुपये केंद्र से मिले

मेट्रो, पुलिस, यूनिवर्सिटी, डीडीए, एनडीएमसी पर खर्चा केंद्र सरकार ही करती है

नई दिल्ली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली वालों को गुमराह कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि दिल्ली को केंद्रीय बजट से टैक्स में से हिस्से के रूप में सिर्फ 325 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली को इस बार 1168 करोड़ से ज्यादा रकम आवंटित की गई है। पिछले वर्ष भी इतनी ही राशि दी गई थी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जानबूझकर झूठे बयान जारी करते हैं।

उन्होंने बताया कि 951 करोड़ रुपये टैक्स के हिस्से के अलावा दिल्ली को 200 करोड़ रुपये चंद्रावल वाटर वर्क्स के लिए, 15 करोड़ रुपये आपदा नियंत्रण के लिए और दो करोड़ रुपये 84 दंगा पीड़ितों की मदद के लिए दिए गए हैं। इस तरह कुल राशि 1168 करोड़ रुपए हो जाती है। दोषारोपण से पहले केजरीवाल सरकार को याद रखना चाहिए कि वास्तव में दिल्ली को 1168 करोड़ रुपये ही नहीं मिले, बल्कि दिल्ली पुलिस, मेट्रो, बड़े अस्पताल, डीयू, जेएनयू, इग्नू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीडीए, एनडीएमसी, नेशनल हाईवे और अन्य प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ही खर्च देती है। अगर यह राशि जोड़ ली जाए तो डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक बैठती है।

2023-24 के बजट में ही रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए 3596 करोड़, मेट्रो के लिए अनुमानित 3500 करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए 11,662 करोड़, एम्स के लिए 4134 करोड़, सफदरजंग, लोहिया और अन्य बड़े अस्पतालों के लिए 4062 करोड़, इग्नू के लिए 105 करोड़, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के लिए 175 करोड़, देशभर की केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए 11,528 करोड़ जिसमें डीयू का बड़ा हिस्सा है।

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। शुक्रवार • 3 फरवरी • 2023

बजट से दिल्ली को मिलेगी 1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि : बिधूड़ी

नई दिल्ली (एसएनबी)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को भ्रामक बताते हुए दावा किया है कि केंद्रीय बजट से दिल्ली को कुल करीब 1.5 लाख करोड़ मिला है। उनका तर्क है कि केंद्रीय करों में ही दिल्ली की 951 करोड़ हिस्सेदारी है। इसके अलावा केंद्र सरकार डीडीए, पुलिस, मेट्रो, यूनिवर्सिटी एवं एनडीएमसी पर खर्च करती है। नेता प्रतिपक्ष ने वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया को झूठ बोलने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार को 325 करोड़ नहीं 1168 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

■ मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने जारी बयान में आरोप लगाया है कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि दिल्ली को टैक्स में 951 करोड़ के अलावा 200 करोड़ रुपए चंद्रावल वाटर वर्क्स, 15 करोड़ आपदा नियंत्रण, दो करोड़ 1984 के दंगा पीड़ितों की मदद के लिए दिए हैं। दिल्ली पुलिस, मेट्रो, दिल्ली के अस्पताल, डीयू, जेएनयू, इग्नू, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीडीए, एनडीएमसी, नेशनल हाईवे एवं अन्य प्रोजेक्ट के लिए आवंटित बजट को देखा जाए, तो यह डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा 20 हजार करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। प्रगति मैदान से बनी टनल पर केंद्र ने 920 करोड़ रुपए खर्च किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

IE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 3, 2023
PERS----------DATED----------

With a month to go for first of G20 events, LG asks agencies to speed up preparations

Abhinav.Rajput@timesgroup.com

New Delhi: The LG office on Thursday directed civic bodies to speed up preparations for the upcoming G20 events and ensure the city is ready to host them.

During a review meeting, LG VK Saxena asked officials to address the niggling issues of stray cattle and encroachments. The Delhi Urban Shelter Improvement Board and Railways were urged to clear unauthorised occupation of government land in a "humane" manner after providing rehabilitation.

"MCD has been instructed to ensure footpaths and pedestrian subways are not illegally occupied and ensure their cleanliness," said the LG office.

Social welfare minister RK Anand and representatives of PWD, MCD, DDA and Delhi government departments were present at the meeting.

With nearly one lakh visitors expected for the G20 summit and its related events, the tourism department has been asked to take steps regarding availability of hotel rooms and guest houses. The LG also told the agencies to ensure hassle-free and seamless movement of travellers at airports, railway stations and bus terminals.

In the past, there have been cases of long queues at the Delhi airport, leading to increased waiting time for passengers.

"Apart from training Uber drivers, their payment portals will be made compatible with international cards as most visitors have access to the app and use credit cards," said a senior official in the LG office.

A special drive will be undertaken by the concerned agencies to check the stray menace, including dogs, cattle, monkeys and pigeons.

MCD had earlier flagged that unchecked entry from neighbouring states and lack of means to identify owners were among the main reasons for the stray cattle menace in the city. In the past few years, several incidents were reported in which bikers collided with abandoned cattle on roads.

The LG office also said the departments have been asked to fix long-pending issues of public concern, such as road repairs and fixing loose hanging wires.

Specific tasks have been assigned to 26 agencies, out of which 24 submitted their action plans for consideration at the meeting, the LG office said.

Beginning March 1, Delhi will host eight major G20 events, including the summit in September in which the heads of states will gather. In the run-up to the main event, a vintage car rally, a cyclothon, an electric car rally, a golf tournament and a film festival will be organised.

Hindustan Times
NEW DELHI
FRIDAY
FEBRUARY 03, 2023

BJP MLA seeks E Delhi body be formed anew, moves HC

Risha Chitlangia
risha.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: Bharatiya Janata Party (BJP) legislator Abhay Verma has approached the Delhi high court, seeking directions to the Delhi government to reconstitute the Trans-Yamuna Area Development Board (TYADB).

In his writ petition filed on January 27, the Laxmi Nagar MLA said the board was last constituted in July 2015, but after the 2020 assembly elections, it was not reconstituted.

The petition also alleged the Aam Aadmi Party government in Delhi has been allocating ₹100 crore annually to the board, but the funds can't be utilised.

"The ₹100 crore funds allocated by the government in the past two financial years have lapsed. In the current financial year also, no project has been sanctioned as the board has not been constituted. Development in east and north east Delhi areas has been badly affected due to this," said Verma.

TYADB WAS SET UP TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF TRANS-YAMUNA REGION ON A PAR WITH THE REST OF THE CAPITAL

A Delhi government spokesperson did not respond to requests for comment.

TYADB was first constituted by the Delhi government in March 1994 to ensure the planned development of the densely populated trans-Yamuna region, and bring it on par with other regions in the Capital.

Its members comprise all MLAs and the two MPs from the trans-Yamuna area, and government officials from agencies such as the Public Works Department, the Delhi Jal Board, and the Delhi Development Authority, among others.

Accusing the AAP of playing politics over the issue, BJP MLA Ramvir Singh Bidhuri, who is the leader of the opposition in the Delhi assembly, said when the AAP won the 2015 elections with 67 out of 70 seats, it had constituted the TYADB. However, now that the board will include six BJP MLAs and two BJP MPs, the AAP is delaying the process, he alleged.

"Why should the public suffer?... "They are doing petty politics. In the last three years, the government has not made any plan for the development of this area," said Bidhuri.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 3 फरवरी 2023 --DATED----------

केंद्र के बजट पर झूठ बोल रही है दिल्ली सरकार : बिधूड़ी

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में सियासत अब केंद्र सरकार के बजट को लेकर गरमाया है। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये मिले हैं। लेकिन, बीजेपी नेता इससे इनकार करते हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार के आरोपों पर कहा कि बजट में दिल्ली को 325 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि डेढ़ लाख करोड़ रुपये मिले हैं।

बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केंद्र सरकार के बजट को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। दिल्ली सरकार यह कह रही है कि केंद्रीय बजट से टैक्स में से हिस्से के रूप में सिर्फ 325 करोड़ रुपये ही मिले हैं। जबकि असलियत यह है कि इस बार दिल्ली को 1168 करोड़ रुपये मिले हैं। 951 करोड़ रुपये टैक्स हिस्से के अलावा दिल्ली को 200 करोड़ रुपये चंद्रावल वॉटर वर्क्स, 15 करोड़ रुपये आपदा नियंत्रण, 2 करोड़ रुपये 1984 के दंगा पीड़ितों के मदद के लिए मिले हैं। यह राशि कुल 1168 करोड़ रुपये है।

> बिधूड़ी ने कहा, बजट में दिल्ली को 325 करोड़ नहीं, बल्कि डेढ़ लाख करोड़ रुपये मिले हैं

उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस, मेट्रो, दिल्ली के बड़े-बड़े अस्पतालों, डीयू, जेएनयू, इग्नू जैसे दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीडीए, एनडीएमसी, नैशनल हाइवे व दिल्ली से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र सरकार ही अपने बजट से पैसे देती है। अगर इन सभी पैसों को मिला दिया जाए, तो दिल्ली को बजट से करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये मिले हैं। 2023-24 के बजट में ही रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए 3596 करोड़, मेट्रो के लिए अनुमानित 3500 करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए 11 हजार 662 करोड़, एम्स के लिए 4134 करोड़, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और अन्य बड़े अस्पतालों के लिए 4062 करोड़, इग्नू के लिए 105 करोड़, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्स के लिए 175 करोड़, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयो के लिये 11528 करोड़ जिसमें डीयू का बड़ा हिस्सा है, बजट में प्रावधान किया गया है।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 3, 2023

3 yrs since fresh norms, Delhi yet to notify a single wetland

Kushagra.Dixit
@timesgroup.com

New Delhi: Three years after the central government issued a fresh set of guidelines for conservation of water bodies, the city is still waiting for its first legally protected wetland.

While some wetlands handpicked by Delhi Wetland Authority (DWA) for rejuvenation and notification in August 2021 are being vetted, only one of 1,040 wetlands has been proposed for notification. None has been notified yet.

Even as various agencies and NGOs use the occasion of World Wetlands Day, marked annually since 2022 on February 2, to spread awareness, the momentum to uplift and enhance the current state of the city's waterbodies seems lost.

However, officials said they have recently written to DDA, the land-owning agency of the prioritised wetlands, to speed up the vetting process so that more wetlands can be proposed for legal protection. "We can then draw up an action plan after which it can be proposed for notification to the Centre," said a Delhi government official.

Officials said they had recently written to DDA, the land-owning agency of the prioritised wetlands, to speed up the vetting process so that more wetlands could be proposed for legal protection

DWA had in August 2021 marked 1,040 wetlands belonging to 16 departments like revenue, DDA and MCD. In January last year, it shortlisted 20 wetlands and later prioritised four of those — Sanjay Lake, Welcome Jheel, Tikri Khurd Lake and Smriti Van (Vasant Kunj) – for legal protection. The technical team on wetlands recommended only Sanjay Lake to Delhi government for notification while vetting and other issues, including encroachment and ownership, are being addressed for the other three waterbodies. Officials are yet to begin work on 1,037 wetlands, a member from the technical team said.

The lieutenant governor had also set a deadline to recommend the wetlands for notification by August 2022 and ensure notification by December 2022, which is still pending.

According to experts, in urban spaces, a notification can save wetlands from encroachment and sewage disposal. "There is a provision of do's and don'ts. Many wetlands have been encroached upon. Once a wetland is legally notified, it is monitored and protected," said Faiyaz A Khudsar, scientist in-charge of DDA's biodiversity park programme.

Meanwhile, this year's World Wetland Day was marked at Yamuna Biodiversity Park and had the theme "It's Time to Save Wetlands". Rajiv Kumar Tiwari, principal commissioner, DDA, stressed on area-specific interventions for arid/semi-arid, floodplains, grasslands, forests for plantation and restoration.